UPSC-CSE
2027/28
DAILY
CURRENT AFFAIRS
ONE STOP SOLUTION
By Faiyaz Sir
The Indian EXPRESS
THE HINDU
pib
PRESS INFORMATION BUREAU
13
AUGUST
COMPLETE COVERAGE
EXAM FOCUSED
ANALYSIS MADE EASY
STATIC + CURRENT INTEGRATION
STAY AHEAD
STAY PREPARED

“

मैं **सही निर्णय** लेने
में विश्वास नहीं करता,
मैं **निर्णय** लेकर
उसे **सही बनाने** में
विश्वास करता हूँ।

”

— रतन टाटा —

आज क्या पढ़ेंगे?

1. सड़क से डिजिटल पोर्टल तक: सीपीग्राम और सुशासन का नया युग

2. महत्वपूर्ण तथ्य

PIB Backgrounder

Azadi Ka Amrit Mahotsav

केंद्रीकृत जन शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम)

CPGRAMS

शिकायत निवारण तंत्र

सड़क से डिजिटल पोर्टल तक: सीपीग्राम और सुशासन का नया युग

स्रोत : PIB

चर्चा में क्यों?

सीपीग्राम (CPGRAMS) ने डिजिटल नवाचार और संस्थागत सुधारों के माध्यम से भारत में जन शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया को पूरी तरह बदल दिया है। यह प्रणाली सभी केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक मंच पर जोड़कर शिकायतों का समयबद्ध एवं प्रभावी समाधान को सुनिश्चित करती है।

परिचय एवं पृष्ठभूमि

सीपीग्राम क्या है

यह प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग का एक प्रमुख ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। यह विभाग कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत आता है।

मूल उद्देश्य

देश के किसी भी कोने से नागरिक को केंद्र या राज्य सरकार के विभागों के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज कराने और उसकी लाइव ट्रैकिंग की सुविधा देना।

बदलाव का दायरा

सड़क पर होने वाले संघर्षों, कागजी दफ्तरों और लंबी कतारों से निकालकर शिकायत निवारण तंत्र को सीधे मोबाइल और डिजिटल पोर्टल तक पहुंचा दिया गया है।

सीपीग्राम: विकास, कार्यप्रणाली और वर्तमान स्थिति

27L

शिकायत निस्तारण 2024

वर्ष 2014 में जहां लगभग 3.01 लाख शिकायतों का निस्तारण हुआ था, वहीं वर्ष 2024 में यह संख्या बढ़कर लगभग 27 लाख (लगभग नौ गुना वृद्धि) हो गई है।

15

औसत समाधान दिन

केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में शिकायतों के निपटारे में लगने वाला औसत समय 2014 के 157 दिनों से घटकर 2025 में केवल 15 दिन (जून 2026 तक 14 दिन) रह गया है।

1.11L

अधिकारियों की संख्या

शिकायत निवारण अधिकारियों की संख्या 2014 के 10,232 से बढ़कर 2025 तक 1.11 लाख से अधिक हो गई है।

शिकायत दर्ज करने के माध्यम

पोर्टल

pgportal.gov.in

मोबाइल ऐप

उमंग ऐप से जुड़े मोबाइल ऐप

सामान्य सेवा केंद्र

5 लाख से अधिक सामान्य सेवा केंद्रों (CSC)

डाक

डाक के माध्यम से शिकायतें दर्ज कराई जा सकती हैं।

समय-सीमा और 10-चरणीय सुधार कार्यक्रम

अगस्त 2024 के नए दिशा-निर्देशों के तहत शिकायतों के निवारण की समय-सीमा को घटाकर 21 दिन कर दिया गया है।

किन मामलों पर विचार नहीं होता: आरटीआई (RTI), न्यायालय में विचाराधीन मामले, धार्मिक मामले, और सरकारी कर्मचारियों की सेवा संबंधी/अनुशासनात्मक शिकायतें इसके दायरे से बाहर हैं।

10-चरणीय सुधार कार्यक्रम और तकनीकी नवाचार

सीपीग्राम 7.0 और स्वचालित मार्ग निर्धारण

इसके विस्तार से शिकायतों को संबंधित अधिकारी तक स्वतः (Automated Routing) पहुँचाने की व्यवस्था हुई है, जिससे मैन्युअल प्रक्रिया समाप्त हो गई है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग

इसके उपयोग से वास्तविक समय में विश्लेषण, पैटर्न की पहचान और समस्याओं के मूल कारणों का पता लगाया जाता है।

भाषाई समावेशिता और प्रमुख पहलें

भाषाई समावेशिता

अंग्रेजी के अतिरिक्त 22 अनुसूचित भाषाओं में शिकायत दर्ज करने की सुविधा है। 'भाषिणी' के एकीकरण से अधिकारी नागरिकों की अपनी भाषा में उत्तर देने में सक्षम हैं।

समाधान दीदी (30 मई 2026)

यह AI-आधारित वॉइस चैटबॉट है, जो नागरिकों को बोलकर अपनी भाषा में बिना किसी जटिल प्रक्रिया के शिकायत दर्ज करने की सुविधा देता है।

अन्य प्रमुख पहलें

शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक (GRAI), प्रतिपुष्टि कॉल सेंटर, 'एक राष्ट्र–एक पोर्टल' और डेटा रणनीति इकाई।

सुशासन के नए युग में सीपीग्राम की विशेषताएं

पारदर्शिता और जवाबदेही

हर शिकायत को एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, जिससे अधिकारी टालमटोल नहीं कर सकते।

एआई और डेटा एनालिटिक्स

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके शिकायतों का वर्गीकरण, भावनाओं की पहचान और बार-बार आने वाली समस्याओं के मूल कारणों का पता लगाया जाता है।

समयबद्ध समाधान

मामलों के निपटान के लिए निश्चित समय-सीमा तय की गई है, जिससे प्रशासनिक उदासीनता में कमी आई है।

फीडबैक तंत्र और मुख्य चुनौतियां

फीडबैक तंत्र: समाधान के बाद नागरिकों से फीडबैक लिया जाता है, जिससे सिस्टम की गुणवत्ता और सुधरती है।

मुख्य चुनौतियां

डिजिटल विभाजन (Digital Divide)

ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में इंटरनेट और डिजिटल साक्षरता की कमी के कारण सभी नागरिक इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।

गुणवत्तापूर्ण निस्तारण

कई बार अधिकारी सिर्फ औपचारिकता पूरी करने के लिए मामले बंद कर देते हैं, जिससे मूल समस्या बनी रहती है।

राज्यों के पोर्टल्स के साथ समन्वय

केंद्र और विभिन्न राज्यों के ग्रीवांस पोर्टल कई बार पूरी तरह एकीकृत नहीं हो पाते हैं।

आगे की राह

1 सशक्त डिजिटल साक्षरता

कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSC) और ग्राम पंचायतों के माध्यम से वंचित वर्ग को पोर्टल का उपयोग सिखाना।

2 उत्तरदायित्व निर्धारण

फर्जी या सतही रूप से बंद की जाने वाली शिकायतों पर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय करना।

3 एकीकृत मंच

वन नेशन-वन ग्रीवांस प्लेटफॉर्म को और अधिक मजबूत करना ताकि राज्य और केंद्र स्तर के सभी विभाग एक ही जगह पर जुड़ सकें।

निष्कर्ष

सीपीग्राम केवल एक शिकायत निवारण मंच नहीं है, बल्कि यह 'विकसित भारत@2047' के विजन को प्राप्त करने का एक प्रमुख प्रशासनिक साधन है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता, भाषाई समावेशिता और समयबद्ध निगरानी के प्रभावी उपयोग के माध्यम से यह प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति की आवाज भी सुनी जाए और उस पर त्वरित कार्रवाई हो।

UPSC PYQ

Q. भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम के प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन-से हैं? (2018)

1. भारत की अपनी इंटरनेट कंपनियों का गठन करना जैसा कि चीन ने किया है।
2. एक नीतिगत ढांचे की स्थापना करना ताकि बड़े डेटा को एकत्र करने वाली विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को हमारे राष्ट्रीय भौगोलिक क्षेत्रों के अंदर अपने डेटा केंद्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।
3. हमारे कई गांवों को इंटरनेट से जोड़ना और हमारे देश के कई स्कूलों, अस्पतालों और सार्वजनिक स्थानों पर वाई-फाई लाना।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a)

केवल 1 और 2

(b)

केवल 3

(c)

केवल 2 और 3

(d)

1, 2 और 3

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

> प्रश्न: "केंद्रीकृत जन शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) ने पारंपरिक प्रशासनिक व्यवस्था को एक उत्तरदायी, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित डिजिटल इकोसिस्टम में बदल दिया है।" भारत में सुशासन को बढ़ावा देने में इस प्रणाली की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए तथा इसके समक्ष मौजूद तकनीकी एवं संरचनात्मक चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)

महत्वपूर्ण तथ्य

भारत सरकार
पत्र सूचना कार्यालय

हमारे बारे में ▾ | प्रेस विज्ञप्ति ▾ | गैलरी ▾ | अनुसंधान इकाई ▾ | मीडिया सुविधाएं ▾ | आर्काइव ▾ | तथ्यों की जांच ▾ | उन्नत खोज

होम / All Factsheet / Factsheet Details

Economy

79 INDEPENDENCE DAY

भारत में वित्तीय समावेशन: हर नागरिक को बैंकिंग सुविधा, प्रत्येक परिवार का सशक्तिकरण

प्रविष्टि तिथि: 12 AUG 2026 16:23 PM

प्रस्तावना

वित्तीय समावेशन भारत के एकसमान विकास के दृष्टिकोण का केंद्रबिंदु है। बीते एक दशक में, भारत ने बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, क्रेडिट, बीमा, पेंशन और निवेश के अवसरों तक पहुंच का विस्तार किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और नागरिक-केंद्रित सुधारों ने इस परिवर्तन को गति प्रदान की है। भारत ने सार्वभौमिक बैंक खाता स्वामित्व से आगे बढ़कर औपचारिक वित्तीय प्रणाली में सक्रिय भागीदारी की ओर कदम बढ़ाया है। इस बदलाव ने लाखों परिवारों, उद्यमियों और व्यवसायों का सशक्तिकरण किया है।

YouTube Homework

+ प्रधानमंत्री जन धन योजना –

महत्वपूर्ण तथ्य

- भारत में **Financial Inclusion (वित्तीय समावेशन)** का मतलब है— हर व्यक्ति, विशेषकर गरीब, ग्रामीण, महिला और वंचित वर्ग को **बैंकिंग, बचत, ऋण, बीमा, पेंशन और डिजिटल भुगतान** जैसी वित्तीय सेवाओं तक सस्ती और आसान पहुँच देना।

सरकार द्वारा प्रमुख पहल

पहल	मुख्य उद्देश्य
1. PM Jan Dhan Yojana (PMJDY), 2014	बिना बैंक खाते वाले लोगों को **Zero-balance bank account**, RuPay Card और overdraft सुविधा देना। (Department of Financial Services)
2. Business Correspondent/Bank Mitra	गाँवों और दूर-दराज क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएँ पहुँचाना। (Department of Financial Services)
3. Direct Benefit Transfer (DBT)	सरकारी सब्सिडी और लाभ सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजना, जिससे leakage कम हो। PMJDY खाते DBT के लिए eligible हैं। (Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana)
4. PMJJBY	कम प्रीमियम पर **जीवन बीमा** उपलब्ध कराना; वर्तमान में ₹2 लाख का life cover। (Department of Financial Services)
5. PMSBY	गरीब एवं सामान्य वर्ग को कम लागत में **दुर्घटना बीमा** उपलब्ध कराना।
6. Atal Pension Yojana (APY)	असंगठित क्षेत्र के लोगों को **वृद्धावस्था में पेंशन सुरक्षा** देना। (Department of Financial Services)
7. PM MUDRA Yojana	छोटे उद्यमियों, दुकानदारों और micro enterprises को **collateral-free institutional credit** उपलब्ध कराने में मदद। (Department of Financial Services)
8. Stand-Up India	SC/ST एवं महिला entrepreneurs को बैंक ऋण तक पहुँच बढ़ाना। (Department of Financial Services)
9. Digital India + UPI	डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देकर बैंकिंग और payment services को आसान बनाया।
10. Financial Literacy	लोगों को बैंक खाते, बीमा, पेंशन, डिजिटल भुगतान और अन्य financial products के बारे में जागरूक करना। PMJDY में financial literacy भी प्रमुख घटक है। (Department of Financial Services)
11. SHG–Bank Linkage	Self Help Groups, विशेषकर महिलाओं को formal banking और credit से जोड़ना।
12. Jan Suraksha Framework	PMJDY को **बीमा + पेंशन** योजनाओं से जोड़कर व्यापक social-security coverage देना। (Department of Financial Services)

महत्वपूर्ण तथ्य

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु को वार्षिक रिपोर्ट-2024-25 प्रस्तुत की

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आयोग से अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षा उपायों और कल्याणकारी उपायों के अधिक प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा संस्थागत तंत्रों को मजबूत और सुव्यवस्थित करने हेतु उपाय तैयार करने का आग्रह किया

प्रविष्टि तिथि: 12 AUG 2026 8:28PM by PIB Delhi

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) ने आज राष्ट्रपति भवन में भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु को 2024-25 के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की।

यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों के कामकाज पर संवैधानिक जनादेश के अनुरूप है। इसमें अनुसूचित जातियों के प्रभावी कार्यान्वयन के साथ-साथ संरक्षण, कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा उठाए जाने वाले उपायों के लिए सिफारिशें शामिल हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य

- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) ने अपनी **वार्षिक रिपोर्ट (Annual Report 2024–25)** राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी है।
- आयोग के अध्यक्ष **किशोर मकवाना** की अगुवाई वाले प्रतिनिधिमंडल ने संविधान के **अनुच्छेद 338 (Article 338)** के तहत यह रिपोर्ट प्रस्तुत की।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु और समीक्षा क्षेत्र

- यह रिपोर्ट देश भर में अनुसूचित जातियों के संवैधानिक अधिकारों, कल्याणकारी योजनाओं और सामाजिक-आर्थिक स्थिति का व्यापक विश्लेषण प्रदान करती है:

1. संवैधानिक सुरक्षा उपायों (Safeguards) की समीक्षा

- आयोग ने केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा SC समुदाय के लिए लागू की जा रही योजनाओं का जमीनी स्तर पर (Spot Visits और Consultations) समीक्षा डेटा पेश किया है।
- इसमें अत्याचार निवारण अधिनियम (PoA Act), नौकरियों व शिक्षा में आरक्षण (Roster Systems) के सही क्रियान्वयन का खाका प्रस्तुत किया गया है।

2. शिकायतें और पेंडेंसी (Backlog Issues)

- रिपोर्ट में आयोग के सामने आई शिकायतों (Service Matters, भूमि विवाद, और अत्याचार संबंधी मामलों) के निपटारे की स्थिति बताई गई है।
- **ऑनलाइन पोर्टल (e-GMP):** डिजिटल शिकायतों (e-Grievance) को तेजी से निपटाने के लिए नए पारदर्शी तंत्र के प्रभाव को रेखांकित किया गया है।

3. राष्ट्रपति द्वारा दिए गए निर्देश

- रिपोर्ट प्राप्त करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आयोग को निर्देश दिया कि:
- SC समुदाय के कल्याण और अधिकारों की सुरक्षा के लिए जो **मौजूदा संस्थागत ढांचा (Institutional Mechanisms)** है, उसे और अधिक मजबूत और सुव्यवस्थित (Streamline) किया जाए।
- कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक बिना किसी प्रशासनिक देरी के पहुंचे।

NCSC के बारे में त्वरित संवैधानिक तथ्य

- **संवैधानिक प्रावधान:** भारतीय संविधान का **अनुच्छेद 338** (89वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा NCSC और NCST को अलग किया गया था)।
- **संरचना:** 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य (राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त)।
- **शक्तियां:** किसी मामले की जांच करते समय आयोग को **सिविल कोर्ट (Civil Court)** की शक्तियां प्राप्त होती हैं।
- **संसदीय प्रक्रिया:** राष्ट्रपति इस वार्षिक रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में **'कार्रवाई ज्ञापन' (Action Taken Memorandum - ATM)** के साथ रखवाते हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य

Retail inflation hits 19-month high in July as fuel prices rise

T.C.A. Sharad Raghavan
NEW DELHI

Retail inflation in India rose to a 19-month high of 4.45% in July, driven up by high food and fuel prices, official data released on Wednesday showed.

The Consumer Price Index (CPI) data released by the Ministry of Statistics and Programme Implementation showed that transport, food, and restaurant and accommodation services became costlier in July, while inflation in other services such as healthcare and recreation cooled marginally.

FULL REPORT ON
» PAGE 4

Steep climb

Retail inflation rose to a 19-month high of 4.45% in July, driven by higher food and fuel prices

Retail inflation hits 19-month high as food, fuel prices rise

T.C.A. Sharad Raghavan
NEW DELHI

Retail inflation in India rose to a 19-month high of 4.45% in July, driven up by higher food and fuel prices, official data released on Wednesday showed.

The Consumer Price Index (CPI) data released by the Ministry of Statistics and Programme Implementation showed that transport, food, and restaurant and accommodation services, became costlier in July, while inflation in other services such as healthcare and recreation sports and culture, cooled marginally.

The CPI series was updated earlier this year, with a new base year of 2024. As a result, while there is historical data for the overall index that goes back to August 2021, sector-wise data is available only from January 2026 onwards. Inflation in the food and beverages category quickened to 5.2% in July 2026 from 5.09% a month earlier.

According to Rajeev Sharan, Head of Research at Brickwork Ratings, this was driven by "fresh spikes in onion and garlic alongside persistently high ginger prices, even as potato and tomato swung into deflation". The expectation ahead is that food inflation will rise further, Madan Sabnavis, chief economist at the Bank of Baroda said.

Monsoon impact

"While the monsoon has recovered substantially in July, there has been news of crop damage," Mr. Sabnavis said. "This, combined with a longer cropping period and hence harvest, will push up prices of pulses. Global prices of edible oils are also high which is being felt in domestic markets."

Driven by higher food and fuel prices, inflation in the restaurants and accommodation services segment quickened to 7.7% in July, the highest this year, up from a previous yearly-high of 6.9% in June.

"The war impact on prices can be seen from higher inflation for restaurants and food services where higher fuel prices have made units increase prices," Mr. Sabnavis explained. "While there is some normalisation in supply of fuel, prices remain where they are and tend to be inelastic in downward direction."

Inflation in the transport sector also quickened to 4.4% in July 2026 from 4.3% in June.

There were, however, some services that saw inflation easing in July. The health segment, for example, saw inflation cooling to 1.3% in July 2026 from 1.4% in June. Inflation in this segment has been falling since February 2026.

The other segment that saw inflation easing was the 'recreation, sport and culture' category to 1.6% in July 2026 from 1.75% a month earlier.

While inflation in the 'personal care, social protection and miscellaneous goods & services' category – which includes gold and silver purchases – remained in double digits at 14.8% in July 2026, it was the lowest level recorded so far this year.

CPI – 2024
MoSPI - NSO
WPI – 2022-23
PPI – 15 June 2026
पहली बार लागू
IIP – 2022-23
Index of 8 Core Industries
Index of 8 Core Industries – NSO
Iron लौह अयस्क
9
ISP – 2022-23
14 July-2026
Index of Services Production

Economy

YouTube Homework

→ महंगाई क्या है
→ प्रकार
→ मापने के उपकरण
→ नियन्त्रित करने के लिए सरकार के प्रकार
RBI

महत्वपूर्ण तथ्य

Inflation (मुद्रास्फीति) क्या है?

- **Inflation** का अर्थ है अर्थव्यवस्था में **वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में लगातार वृद्धि** होना, जिसके कारण **पैसे की क्रय शक्ति (Purchasing Power) घट** जाती है।

Index	Full Form	Base Year	Publisher/Agency	क्या मापता है?
CPI	Consumer Price Index	**2012 = 100**	**NSO, MoSPI**	Retail/Consumer prices
WPI	Wholesale Price Index	**2011-12 = 100**	**Office of Economic Adviser (OEA), DPIIT**	Wholesale prices of goods
PPI	Producer Price Index	**भारत में official operational PPI का सामान्य base year नहीं**	भारत में अभी CPI/WPI की तरह official headline index नहीं	Producer-level prices
IIP	Index of Industrial Production	**2011-12 = 100**	**NSO, MoSPI**	Industrial production
ISP	Index of Services Production	**कोई प्रमुख official all-India ISP नहीं**	—	Services output के लिए अलग-अलग indicators
8 Core Industries Index	Index of Eight Core Industries	**2011-12 = 100**	**Office of Economic Adviser, DPIIT**	8 core industries का production

महत्वपूर्ण तथ्य

Charges made against Justice Varma 'proved', says probe report

Sandeep Phukan
NEW DELHI

A three-member inquiry committee constituted by Lok Sabha Speaker Om Birla has found the charges "proved" against former Delhi High Court judge Justice Yashwant Varma over the discovery of burnt currency at his official residence, holding that his explanations were "evasive and unsatisfactory".

The committee's report, tabled in both Houses of Parliament on Wednesday, said Justice Varma had failed to provide a satisfactory explanation regarding the presence, source, or ownership of the cash found in the storeroom of his official residence.

Justice Yashwant Varma

Justice Varma's explanation did not demonstrate the "candour, transparency and institutional responsibility" expected of a judge, the report said. "It remained evasive and unsatisfactory when tested against the evidence of independent official witnesses and corroborative material," the committee noted.

The panel also found that material evidence at the site had not been properly secured or preserved, and that the evidentiary condition of the storeroom had been disturbed before it was lawfully sealed and inspected.

The panel was headed by Supreme Court judge Justice Aravind Kumar, and had Chief Justice of the Bombay High Court Justice Shree Chandrashekhar and senior advocate of the Karnataka High Court B.V. Acharya as members.

In its consolidated findings on the three articles of charge, the panel recorded: "The Committee therefore records its final findings that Articles of charges I, II and III are proved."

Sources indicated that the government may consider carrying forward the process of removal against him since removal proceedings started before he resigned.

'INQUIRY CANNOT JUST END'

» PAGE 4

YouTube Homework

Supreme Court & It's Recent Judgement

अन्य कौन से संवैधानिक अधिकारी हैं, जिन्हें SC के न्यायाधीशों के समान हटाया जाता है?

महत्वपूर्ण तथ्य

Supreme Court के Judge को हटाने की प्रक्रिया

- भारत में Supreme Court के Judge को हटाना **बहुत कठिन और संवैधानिक रूप से सुरक्षित प्रक्रिया** है, ताकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रहे। इसका आधार मुख्यतः **Article 124(4) और 124(5)** तथा **Judges (Inquiry) Act, 1968** है।

Removal के Grounds

- Supreme Court के Judge को केवल दो आधारों पर हटाया जा सकता है:
- **Proved Misbehaviour — सिद्ध कदाचार**
- **Incapacity — अक्षमता**
- सिर्फ सरकार या राष्ट्रपति की इच्छा से Judge को नहीं हटाया जा सकता।

Parliament में Removal Motion

- Removal की प्रक्रिया **Parliament** से शुरू होती है।
- Motion लाने के लिए:
- **Lok Sabha:** कम-से-कम **100 MPs**
- **Rajya Sabha:** कम-से-कम **50 MPs**
- Motion संबंधित Presiding Officer को दिया जाता है।
- Lok Sabha में ⟶ **Speaker**
- Rajya Sabha में ⟶ **Chairman**
- Presiding Officer motion को **admit या reject** कर सकता है।

3-Member Inquiry Committee

- Motion admit होने के बाद **3 सदस्यीय Inquiry Committee** बनाई जाती है।
- इसमें होते हैं:
- Supreme Court का एक Judge
- किसी High Court का Chief Justice
- एक **distinguished jurist**
- यह Committee Judge के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जाँच करती है।
- Judge को अपना बचाव करने का अवसर भी दिया जाता है।

Committee की Report

- Committee अपनी रिपोर्ट Parliament को देती है।
- **अगर आरोप सिद्ध नहीं हुए:**
- आगे की removal proceedings समाप्त हो जाती हैं।
- **अगर आरोप सिद्ध हो गए:**
- Motion Parliament में आगे बढ़ता है।

महत्वपूर्ण तथ्य

दोनों सदनों में Special Majority

- अब **Lok Sabha और Rajya Sabha दोनों** को Motion पास करना होगा।
- प्रत्येक सदन में:
- **Special Majority =**
- **Total Membership का Majority**

  \+

  Present & Voting Members का कम-से-कम 2/3
- यानी दोनों conditions **एक साथ** पूरी होनी चाहिए।

President की भूमिका

- जब दोनों Houses Motion पास कर देते हैं, तो दोनों सदन **एक ही Parliamentary Session में** President को removal का address प्रस्तुत करते हैं।
- इसके बाद **President removal order जारी करते हैं।**
- इसलिए technically Judge को **President के order से हटाया जाता है**, लेकिन President यह कार्रवाई **दोनों Houses की constitutional प्रक्रिया पूरी होने के बाद** करते हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य

Amid Opposition protests, Lok Sabha clears Mines and Minerals Amendment Bill

2026
अधिनियम

The Hindu Bureau
NEW DELHI

Tumultuous scenes: Union Ministers Kiren Rijiju, G. Kishan Reddy, Arjun Ram Meghwal, and others in the Lok Sabha on Wednesday. PTI

Amid vocal protests by Opposition members, the Lok Sabha passed a Bill on Wednesday to amend the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act without a debate.

The Lok Sabha took up the Bill for passage after a couple of adjournments earlier in the day. But almost immediately the Opposition trooped into the Well of the House and started shouting slogans.

Revolutionary Socialist Party MP N.K. Premachandran had strongly opposed the introduction of the Bill, arguing that it was against federalism.

When the Chair, Jagdambika Pal, put the Bill to vote, Opposition members started shouting "Adani, Adani".

After the Bill passed, Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju objected to Opposition MPs crowding the Well of the House. Mr. Rijiju said the government was ready to debate the issue of student protests over the NEET paper leaks and urged the Opposition to start discussion.

He also said Union Home Minister Amit Shah was ready to answer questions and informed the House that Mr. Shah had written to the Speaker seeking a debate.

Meanwhile, Mr. Pal appealed to Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav and senior Congress leader K.C. Venugopal to ask their respective party members to take their seats.

However, Mr. Yadav's attempt to speak proved futile as his microphone was not on and his voice got drowned out in the sloganeering. The House was adjourned till Thursday.

The Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2026, prevents State governments from imposing additional taxes, cesses, or levies on mineral rights and gives the Centre greater control over regulating mineral-laden lands.

Introducing the Bill, Coal and Mines Minister G. Kishan Reddy said divergent fiscal levies by States had created uncertainty in the mineral sector and could raise costs, encourage imports and undermine domestic supply chains.

महत्वपूर्ण तथ्य

हाल ही में संसद द्वारा पारित MMDR संशोधन विधेयक-2026 राजकोषीय संघवाद के लिए चुनौती प्रस्तुत करता है। आप इस सन्दर्भ में क्या सोचते हैं? (250 शब्द)

MMDR Amendment Bill, 2026 क्या है?

- यह **Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (MMDR Act)** में संशोधन का प्रस्ताव है।
- 2026 में Ministry of Mines ने इसके लिए public consultation भी की थी।

मुख्य प्रावधान

- **1. राज्यों की Tax लगाने की शक्ति पर रोक/सीमा**
  सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है—**mineral rights या mineral-bearing lands** पर State Governments द्वारा लगाए जाने वाले **tax, cess या अन्य levies** को सीमित करना। उद्देश्य mining की लागत कम करना और पूरे देश में mineral taxation को अधिक uniform बनाना है।
- **2. Central Government की भूमिका मजबूत**
  Mineral rights पर taxation/levy के मामले में **केंद्र की regulatory भूमिका बढ़ेगी**, जिससे Centre–State fiscal relations पर बहस हो रही है।
- **3. Mining cost कम करने का प्रयास**
  अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग cess/levies के कारण mining projects की लागत बढ़ सकती है। Bill का उद्देश्य इस अतिरिक्त fiscal burden को कम करके **mining को economically viable** बनाना है। uniform – tax
- **4. Mineral production और investment को बढ़ावा**
  कम fiscal burden से mining में investment बढ़ाने और domestic mineral production को बढ़ावा देने का लक्ष्य है। इसका महत्व खासकर **critical minerals** की supply security के संदर्भ में है।
- **5. राज्यों के Revenue पर प्रभाव**
  दूसरी तरफ, जिन राज्यों को mineral-bearing areas से taxes/cess/levies के माध्यम से revenue मिलता है, उनकी **fiscal autonomy और revenue position** प्रभावित होने की आशंका है। यही Bill का प्रमुख federalism concern है।

महत्वपूर्ण तथ्य

In 'era of reels', avoid shortcuts, read autobiographies, Modi tells youth

The Hindu Bureau
NEW DELHI

Prime Minister Narendra Modi on Wednesday urged young people in the "era of reels" not to take shortcuts, and instead read autobiographies of the people they admired to get a unique perspective on historical events.

Speaking at the launch of former President Ram Nath Kovind's autobiography, *Triumph of the Indian Republic: My Life, My Struggles*, he said Mr. Kovind's life showed how determination could help a person overcome adversity and rise to the highest constitutional office.

Mr. Modi appealed to the youth to read autobiographies as such books offered the opportunity to understand a particular period through the life of someone who had experienced it.

"This is the era of reels. Social media influencers often pull you in and take you down certain paths. In this age of shortcuts, let us remember a message often displayed at railway stations: a shortcut will cut you short. This is written because some people have a habit of jumping onto the tracks instead of using the railway bridge. However, if there is a shortcut you should take to get ahead in life, it is to read the autobiography of someone you admire," Mr. Modi said.

Prime Minister Narendra Modi with former president Ram Nath Kovind during the launch of latter's autobiography in New Delhi. PTI

Engaging with Gen Z

His remarks come at a time when the Centre and the Bharatiya Janata Party (BJP) have stepped up efforts to engage with Gen Z on social media.

He highlighted Mr. Kovind's continuing public engagement, saying that the former President had not rested after demitting office, and was working on the simultaneous election initiative, which could, Mr. Modi said, "open a new chapter in Indian democracy". "We need many more young people who would be like Kovind*ji* in future – people who are not defeated by circumstances but possess the determination to overcome every challenge," he said.

Mr. Kovind recalled hardships in his childhood and the values he imbibed from his surroundings.

Lok Sabha Speaker Om Birla, Chief Justice of India Surya Kant, and several Union Ministers attended the event.

महत्वपूर्ण तथ्य

Troubling bill

The FCRA amendments need redrafting in the JPC

The BJP-led government's relentless zeal in over-regulating civil society organisations is on display again in the Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill, 2026, which it had sought to push through Parliament. After strong protests, it has now been referred to a Joint Parliamentary Committee (JPC). In 2020, the government got amendments to the Foreign Contribution (Regulation) Act, or FCRA, passed that barred a registered body from passing funds to another, even one registered under the same Act, and cut the share of foreign funds that could be spent on administration from half to a fifth, among other restrictions. It now proposes to go further still by taking over the assets that the money built, even on the mere lapse of a certificate. Under the Bill, a donee organisation can lose its registration not only when the government cancels it, but when renewal is refused, not applied for, or not granted before the old certificate runs out. As soon as this happens, the organisation's foreign funds and what was built with them will pass to a government-designated authority automatically. The property returns only if the organisation re-registers within a period the government has yet to specify, failing which it is lost for good. According to the Bill, a building put up only partly with foreign money will be taken over in full. The organisation must then apply to get back the share not paid for with foreign money. The Bill does allow for an appeal to a district judge, but only against what the authority does with the property later. The refusal to renew cannot be appealed against, and the organisation will not be entitled to be heard before the refusal is made. In essence, because the authority acts on the Centre's instructions, the Centre can use opaque reasons to withdraw a licence, take over the property, and then direct the body now holding it.

It is not surprising that minority religious institutions have been the most alarmed. This is true of Christian organisations, which run thousands of schools, colleges and hospitals built and sustained with money from churches and congregations abroad. Hundreds marched in Aizawl, Mizoram, under a newly formed council of churches; organisations in Kerala have objected to the Bill; Nagaland's Chief Minister wrote to the Home Minister seeking a parliamentary review; and the Tamil Nadu Assembly has also unanimously resolved that the Centre should withdraw the Bill. The Home Minister has assured church leaders that the Bill will not apply retrospectively, but the text of his own Bill says otherwise. A hospital built decades ago can still be taken over today because a certificate has been allowed to lapse. The JPC, to which the Bill has been sent, should redraft it to provide organisations with an opportunity to be heard before renewal is refused, as well as a right to appeal against such a refusal, among other changes that would make the regulation fair and transparent.

FCRA (A) - Bill - 2026

JPC

YouTube Homework

- NGO
- VO

महत्वपूर्ण तथ्य

FCRA Amendment Bill 2026

- **1. Designated Authority की स्थापना**
- Bill एक **Designated Authority** बनाने का प्रस्ताव करता है।
- इसका काम होगा उन organisations की **foreign contribution और उससे बनाई गई assets** को:
- अपने नियंत्रण में लेना
- उनकी supervision/management करना
- आवश्यकता पड़ने पर उनका disposal करना
- जब organisation का FCRA certificate समाप्त/cancel हो जाए।

- **2. Registration समाप्त होने के नए आधार**
- मौजूदा framework में cancellation/surrender के अलावा Bill स्पष्ट रूप से यह जोड़ता है कि FCRA certificate **cease** हो जाएगा यदि:
- registration की validity समाप्त हो जाए और renewal न कराया जाए
- renewal के लिए application ही न दी जाए
- renewal application **reject** कर दी जाए।
- यानी केवल certificate cancel होना ही महत्वपूर्ण नहीं रहेगा; **expiry/non-renewal भी महत्वपूर्ण trigger** बनेगा।

- **3. Foreign-funded Assets पर Government Control**
- यह Bill का **सबसे controversial provision** है।
- यदि FCRA certificate cease/cancel/surrender होता है, तो organisation के पास मौजूद:
- **Foreign contribution + उससे बनाई गई assets**
- Designated Authority में vest हो सकती हैं।
- इसमें ऐसी assets भी शामिल हो सकती हैं जिन्हें **आंशिक रूप से foreign contribution से बनाया गया हो।**

- **4. Vesting पहले Provisional, फिर Permanent**
- Asset vesting को दो चरणों में समझें:
- **Certificate फिर से मिल गया / renew या restore हो गया**

  ⬇️

  Designated Authority assets/unused foreign contribution वापस करेगा।
- **Certificate restore/renew नहीं हुआ**

  ⬇️

  Vesting **permanent** हो सकती है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- **5. 🛕 Places of Worship के लिए विशेष प्रावधान**
- यदि foreign contribution से बनी asset **place of worship** है, तो Designated Authority को उसकी **religious character बनाए रखना** होगा।
- यह provision इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कई religious/charitable institutions foreign contributions का उपयोग infrastructure बनाने में करते हैं।
-

- **6. Penalty में बदलाव**
- Bill FCRA violation के लिए **maximum imprisonment को 5 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष** करने का प्रस्ताव करता है।
- 👉 यानी Bill में एक तरफ **asset-control mechanism मजबूत** किया जा रहा है, वहीं imprisonment की maximum अवधि कम की जा रही है।

महत्वपूर्ण तथ्य

A timely reset for the Food Security Act

India's food security debate has entered a new phase. Estimates based on India's latest household consumption survey suggest that the share of households unable to afford the ICMR-National Institute of Nutrition (NIN) recommended diet fell from about 52% in 2011-12 to about 25% in 2023-24, affecting 25% of rural and 21% of urban households. This is substantial progress, but crores of households still cannot afford an adequate healthy diet. Poverty, hunger and inability to afford a healthy diet overlap; a modern food-security policy must recognise that they are not identical.

The draft National Food Security (Amendment) Bill, 2026 links Antyodaya Anna Yojana (AAY) entitlements to household size. The policy challenge is to correct inequity without reducing existing foodgrain access, while creating a pathway towards nutrition security.

Designing a fairer entitlement

Priority Households receive 5 kg of foodgrains per person per month, while AAY households receive a flat 35 kg per household. The latter protects smaller and highly vulnerable families but provides progressively less per person as household size grows: a seven-member household receives 5 kg per person and an eight-member household about 4.4 kg, below the Priority Household entitlement. The draft proposes 7 kg per person, capped at 35 kg. This would reduce support for households with one to four members by 20% to 80%, leave those with five or more unchanged, and provide no AAY household with additional foodgrain.

Tamil Nadu illustrates the potential impact. The State government reports that 15.75 lakh of its 18.64 lakh AAY households (84.5%) have fewer than five members. It estimates that the proposal would reduce the monthly AAY allocation from 65,261 tonnes to 42,040 tonnes, a fall of about 35.6%. Although specific to Tamil Nadu, these projections show why household composition and vulnerability must be considered: a smaller household may include an older person living alone, a widow or a person with disability.

As the proposal is taken forward, the existing 35 kg entitlement should be preserved through an explicit no-loss safeguard. Because retaining 35 kg as both the minimum and maximum would leave the per-person formula with no practical effect, support beyond 35 kg for larger or highly dependent households should be examined as a separate policy question using household-consumption evidence, nutritional requirements and transparent fiscal costing.

Entitlement reform must also address coverage. Although the NFSA allows coverage of up to 75% of the rural and 50% of the urban population, its 81.35-crore beneficiary ceiling remains based on Census 2011; about 80 crore people receive free foodgrains. Against the estimated population of 146.4 crore in 2025, this ceiling covers only 55.6%. It should be recalculated when the Census 2027 figures become available. Meanwhile, updated population estimates and deprivation criteria could support a transparent review, with accessible inclusion and appeal mechanisms.

Viswanathan Mohan
Chairman, Madras Diabetes Research Foundation, Chennai

Soumya Swaminathan
Chairperson, M.S. Swaminathan Research Foundation, Chennai

Nijina M. Nazar
Principal Project Scientist, Indian Institute of Technology Madras, Chennai

> The proposed amendment offers an opportunity to preserve the 35 kg AAY entitlement, assess the needs of larger households, and finance a gradual transition toward more diverse and nutritious diets

Protecting grain while diversifying diets

Protecting the grain entitlement does not mean preserving a cereal-only understanding of food security. NFHS-6 (2023-24) found that stunting among children under five fell from 35.5% to 29.3%, but wasting and underweight barely changed, from 19.3% to 19.0% and 32.1% to 31.8%, respectively. Only about 15% of children (six-23 months) receive a minimally adequate diet. Meanwhile, the ICMR-India Diabetes (INDIAB) study estimated that 101 million Indians had diabetes and 136 million had prediabetes in 2021. These figures reflect India's double burden of malnutrition. Maternal undernutrition and low birth weight are associated with greater risk of non-communicable diseases (NCDs) later in life, while present-day diet and other behavioural factors add further risk.

Foodgrain entitlement should not itself be equated with diabetes risk. The concern is that a predominantly cereal-based food basket, when combined with diets already high in carbohydrates and low in protein-rich foods, may reinforce dietary imbalance. The solution is not to reduce essential cereal entitlements, but to finance dietary diversification alongside.

The dietary evidence favours balance over simply increasing or substituting cereals. A 2025 ICMR-INDIAB study of 18,090 adults found carbohydrates supplied 62.3% of daily energy nationally and protein 12%. Adults with the highest carbohydrate intake had 30% higher odds of newly diagnosed type 2 diabetes than those with the lowest intake. Replacing refined cereals with whole-wheat or millet flour was not linked to lower risk when the carbohydrate share remained high. Modelling suggested greater benefit from replacing some carbohydrate calories with protein-rich foods.

These observational and modelled findings cannot establish that changing the Public Distribution System (PDS) basket will prevent diabetes, but caution against treating more grain or millets alone as a complete nutrition policy. The ICMR-NIN's 2024 guidelines recommend that cereals and millets provide at most 45% of energy, with greater contributions from pulses, beans, milk, nuts, vegetables, fruits and other protein sources.

The PDS cannot supply the entire healthy plate; it can best provide affordable, shelf-stable foods. States should be supported to offer pulses, local rice, wheat and millet choices and, where feasible, healthy edible oils. Local production and consumption should guide supply chains and effective Minimum Support Price (MSP) procurement for pulse, millet and oilseed growers. Sustained public investment should link food, nutrition and health systems through complementary programmes: the PDS, Anganwadi services for young children and pregnant or lactating women, and Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman (PM POSHAN) for schoolchildren. These programmes could provide eggs, milk or suitable alternatives where locally acceptable and feasible. Dietary diversification must be separately budgeted, not financed by reducing cereal entitlements. The 2026-27 Union Budget allocates ₹2,27,629 crore to food subsidy, underscoring the need for transparent costing. Additions should be tested through phased State pilots assessing actual consumption, dietary diversity, anaemia and glycaemic risk, household spending, wastage, exclusion and supply feasibility. Pilot evidence can guide fiscally sustainable expansion and help assess potential longer-term health and fiscal benefits.

Linking food access with nutrition support

The NFSA's strength lies in guaranteeing reliable, dignified food access. India has built a formidable delivery network. By the end of 2025, 5.50 lakh of 5.51 lakh fair price shops used electronic point-of-sale devices, while One Nation One Ration Card covered nearly all NFSA beneficiaries. These systems support portability and monitoring but must include reliable offline alternatives, assisted or doorstep access for people with limited mobility, and a clear guarantee that authentication failure will not lead to denial of entitled foodgrains.

Fair price shops could support last-mile nutrition information and referral. Simple multilingual receipt, display, voice and mobile messages could promote dietary diversity, appropriate cereal portions, pulses, healthier oils, and less salt and added sugar. Where feasible, trained health workers could undertake periodic outreach through India's primary-health infrastructure, linking willing adults to government diabetes, hypertension and other NCD services. By June 2026, India had over 1.86 lakh Ayushman Arogya Mandirs, while government data recorded 41.3 crore diabetes screenings. Fair price shop dealers should facilitate information and referral, not diagnose or counsel. Participation must be voluntary, confidential and unrelated to ration eligibility or authentication.

The amendment should therefore be situated within a broader architecture for food and nutrition security, anchored in three safeguards. First, any per-person formula should preserve the existing 35 kg monthly entitlement for every AAY household through an explicit no-loss guarantee. Second, the adequacy of the 35 kg ceiling should be reviewed periodically for larger households and those with high dependency or nutritional needs, using consumption, nutritional and fiscal evidence. Third, dietary diversification must be separately financed and progressively implemented without reducing existing cereal entitlements.

India's next food security reform must protect people from hunger while also addressing the dietary drivers of diabetes and other NCDs. Its success should be judged not only by the tons of grain moved, but by whether vulnerable families can eat enough, eat healthier and obtain their entitlements with dignity.

गरीबी उन्मूलन
→ फ्री खाद्यान
PDS + 80+ Cr.
पोषक
→ NFSA - 2013
→ 80+ Cr.
खाद्यान - अधिकार

महत्वपूर्ण तथ्य

NFSA के तहत कितना अनाज?

- **Priority Households (PHH)**
- प्रत्येक व्यक्ति को:
- **5 kg foodgrains प्रति माह**
- मिलने का entitlement है।
- **Antyodaya Anna Yojana (AAY)**
- एक AAY household को:
- **35 kg foodgrains प्रति माह**
- का entitlement है।

मुख्य अंतर

आधार	PDS	NFSA
पूरा नाम	Public Distribution System	National Food Security Act
प्रकृति	**Distribution System**	**कानून (Act)**
शुरुआत	स्वतंत्र रूप से विकसित हुआ; वर्तमान Targeted PDS 1997	**2013**
उद्देश्य	Subsidised/Free foodgrains का वितरण	Food security को **legal entitlement** बनाना
लाभार्थी	विभिन्न समय पर अलग-अलग categories	ग्रामीण **75%** और शहरी **50%** तक coverage
प्रमुख लाभ	खाद्यान्न वितरण	प्रति व्यक्ति **5 kg/month** foodgrains
Household category	AAY आदि	**Priority Households + AAY**
Legal Right	सामान्यतः नहीं	**हाँ**
वितरण माध्यम	Fair Price Shops	NFSA entitlement भी FPS/PDS के माध्यम से

महत्वपूर्ण तथ्य

→ न्यायिक व्यवस्था –
IPC – BNS
CrPC – BNSS
IEA – BSA
2023

Supreme Court clarifies scope of police custody under BNSS

Court held that Section 187(2) of BNSS enlarges the window during which police custody may be sought

R.K. Vij

The story so far:

The Supreme Court recently held in *The State of Andhra Pradesh vs Suda Suresh Veera Venkata Naga Raju* that Section 187(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS), enlarges the window during which police custody may be sought by the investigating agency. Such custody, under the BNSS is now available in parts, though in aggregate not exceeding 15 days during the first 40 or 60 days of the total permissible period of detention, rather than being confined to the first 15 days of remand alone.

Case under consideration by the SC

In a case of custodial death in which the dead body of the deceased-victim remained untraced, the original hard disks of the CCTV system were yet to be discovered, and discoveries under the Bharatiya Sakshya Adhiniyam (BSA) were imminent, the judicial magistrate granted eight days of police custody, and allowed the accused to nominate two advocates of his choice to be present during custody. Out of the two advocates, one was allowed to be present at any given point of time during investigation. The order stated that 'under no circumstances shall the period of police custody granted under this order be extended'.

While on appeal, the Andhra Pradesh High Court modified some conditions pertaining to the period of police custody and presence of an advocate throughout the probe. The State therefore challenged the above conditions in the Supreme Court on the premise that these directly impinged upon the rights of the investigating officer to conduct unhindered investigation.

The Supreme Court held that the apprehensions expressed by the investigating agency were justified and the statutory scheme under the BNSS which enlarges the window of police custody, must also be borne in mind. A magistrate or a court cannot place an absolute and non-extendable outer limit on custody, since such a limit forecloses recourse to Section 187(2) of the BNSS.

The Court therefore permitted 7 days of (additional) police custody so that the total period of police remand would not exceed 15 days.

Current law on police remand

Section 58 of the BNSS provides that any person arrested by the police without warrant cannot be detained for more than 24 hours, unless authorised by a magistrate under Section 187.

Section 187(2) of the BNSS provides that in case it appears to the investigating officer that the probe cannot be completed within 24 hours, and there are grounds for believing that the accusation is well founded, the magistrate may authorise the detention of the accused for a period not exceeding 15 days in the whole, or in parts, at any time during the initial 40 days or 60 days out of the detention period of 60 days or 90 days.

Section 187(3) provides that the magistrate may authorise the (judicial) detention of an accused person beyond the period of 15 days, if he is satisfied that adequate grounds exist for doing so, for a period exceeding - (i) 90 days, where the investigation relates to an offence punishable with death, imprisonment for life or imprisonment for a term of 10 years or more; (ii) 60 days, where the investigation relates to any other offence. Thus, in case the probe is not completed within the above stipulated time period, the accused person may be released, which is widely known as default bail.

The Supreme Court in the *Suda Suresh* case held that this legislative change was intended to meet situations where fresh facts, discoveries or leads may emerge during the course of investigation. Therefore, the window of police remand was enlarged beyond the initial 15 days, up to 40 days or 60 days of investigation.

Previously, Section 167 of the CrPC provided that the detention of an accused in police custody could not be granted beyond the initial 15 days in the whole. However, during this first period of 15 days the magistrate could alter the nature of the custody from judicial custody to police custody and vice versa.

On the presence of an advocate

Section 38 of the BNSS provides that 'when any person is arrested and interrogated by the police, he shall be entitled to meet an advocate of his choice during interrogation, though not throughout interrogation'.

The top court held that a plain reading of the provision makes it clear that it does not contemplate the continuous, ongoing physical presence of an advocate for the entirety of each interrogation session. The Court held that an unqualified entitlement to continuous presence, would travel beyond what Section 38 BNSS itself contemplates. The Court therefore modified the condition imposed by the High Court and held that such a lawyer shall only be allowed to remain present within the site of interrogation where he can see the respondent-accused.

The Court also held that instead of uninterrupted videography of the transit of the accused between locations, the audio-visual recording of the actual interrogation, and of any proceedings of discovery or recovery undertaken with the accused, will satisfy the requirement.

(R.K. Vij is a former IPS officer.)

187(1) → पुलिस हिरासत और न्यायिक हिरासत
187(3)
अनुच्छेद 22 + BNSS-187

YouTube Homework

- Zero FIR – BNSS 173(1)
- Trial in Absentia – BNSS 356

महत्वपूर्ण तथ्य

- **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 187** इन दिनों कानूनी और प्रशासनिक हलकों में काफी चर्चा में है।
- यह धारा पुराने **CrPC की धारा 167** की जगह लागू की गई है, जो आरोपी को पुलिस रिमांड (Police Custody) पर लेने और डिफ़ॉल्ट ज़मानत (Default Bail) से जुड़े नियम तय करती है।

1. यह चर्चा में क्यों है?

- मुख्य विवाद और चर्चा का कारण **पुलिस रिमांड (Police Custody) के 15 दिनों को लेने की समय सीमा और तरीका** है:
- **पुराना नियम (CrPC Section 167):** गिरफ्तारी के **शुरुआती 15 दिनों के भीतर** ही पुलिस अपनी 15 दिन की कस्टडी ले सकती थी। इसके बाद आरोपी को सिर्फ न्यायिक हिरासत (Judicial Custody/Jail) में ही भेजा जाता था।
- **नया नियम (BNSS Section 187):** अब पुलिस कस्टडी की अधिकतम सीमा तो 15 दिन ही है, लेकिन पुलिस इन 15 दिनों की कस्टडी को **टुकड़ों (Parts/Splits) में** ले सकती है:
  - **60 दिन वाली जांच के मामलों में:** शुरुआती **40 दिनों** के दौरान कभी भी टुकड़ों में 15 दिन की पुलिस कस्टडी ली जा सकती है।
  - **90 दिन वाली जांच के मामलों में:** शुरुआती **60 दिनों** के दौरान कभी भी 15 दिन की पुलिस कस्टडी ली जा सकती है।
- हाल ही में **सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)** ने भी इसकी व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया है कि पुलिस कस्टडी सिर्फ पहले 15 दिनों तक सीमित नहीं रहेगी।

2. BNSS की धारा 187 के मुख्य प्रावधान

प्रावधान	विवरण
24 घंटे का नियम	गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है।
अधिकतम पुलिस कस्टडी	कुल पुलिस कस्टडी **15 दिन** से ज्यादा नहीं होगी।
कस्टडी विंडो (Custody Window)	पुलिस अपनी 15 दिन की कस्टडी शुरुआती 40 या 60 दिनों के दौरान कभी भी मांग सकती है।
डिफ़ॉल्ट ज़मानत (Default Bail)	गंभीर मामलों (10 वर्ष/आजीवन कारावास/मृत्युदंड) में **90 दिन** और अन्य मामलों में **60 दिन** में चार्जशीट न दाखिल होने पर डिफ़ॉल्ट जमानत का अधिकार।
जांच का विस्तार	6 महीने से अधिक जांच खींचने पर **SP (Superintendent of Police) स्तर के अधिकारी** की लिखित अनुमति जरूरी है।

महत्वपूर्ण तथ्य

3. इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क

- 🔹 **समर्थन में तर्क (जांच एजेंसियों का पक्ष):**
- **नई कड़ियों का मिलना:** कई बार मामले के नए मोड़ या नए सबूत 20-25 दिन बाद मिलते हैं। नए नियम के तहत पुलिस आरोपी को दोबारा कस्टडी में लेकर पूछताछ कर सकती है।
- **अस्पताल/बीमारी का बहाना:** पुराने कानून में आरोपी अक्सर शुरुआती 15 दिन अस्पताल में भर्ती होकर पुलिस कस्टडी से बच जाते थे। अब यह पैंतरा काम नहीं करेगा।
- ⚠️ **चिंताएं (कानूनी विशेषज्ञों का पक्ष):**
- **कस्टडी में उत्पीड़न की संभावना:** आरोपी के दिमाग में लंबे समय (40-60 दिन) तक यह डर बना रह सकता है कि उसे दोबारा पुलिस कस्टडी में भेजा जा सकता है।
- **जमानत में बाधा:** जब तक 40 या 60 दिनों की विंडो खुली है, तब तक नियमित जमानत (Regular Bail) मिलना थोड़ा कठिन हो सकता है।

महत्वपूर्ण तथ्य

Nighttime blitz damaged Russia's Black Sea Naval base: Zelenskyy

Anti-ship missiles, jet-powered aerial drones and sea drones conduct strikes on naval base in Novorossiysk, says Ukrainian leader; he warns of broader strategic moves by Russia; Moscow claims its air defences shot down more than 500 drones

Associated Press
KYIV

Ukrainian anti-ship missiles, jet-powered aerial drones and sea drones blitzed a major Russian Naval base on the Black Sea coast in a "unique" nighttime operation, Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy said on Wednesday.

Cutting-edge drones developed by Kyiv since Russia invaded more than four years ago have repeatedly targeted Russian ships in the Black Sea, including warships and oil tankers.

Extensive loss: A damaged private house following a Ukrainian drone strike in Novorossiysk in Russia on Wednesday. REUTERS

Both countries have Black Sea shorelines.

Ukraine's uncrewed fleet has succeeded in limiting the movements of Russia's once-dominant Black Sea navy, Kyiv officials say, in one of the country's biggest accomplishments of the war.

But Ukrainian officials reckon that Russian President Vladimir Putin is bent on prosecuting the invasion, despite his bigger army's slow and costly progress on the battlefield and U.S. diplomatic efforts to find a settlement.

Mr. Putin is planning "an additional rapid mobilisation of several hundred thousand Russians by the end of the year," Mr. Zelenskyy said on social media late Tuesday, citing Ukrainian intelligence reports.

The Ukrainian military "carried out a unique operation targeting the Naval base in Novorossiysk – the last major stronghold of the Russian fleet in the Black Sea," Mr. Zelenskyy said. The attack struck air defences, piers and other infrastructure in the Krasnodar region, he added.

Krasnodar region Gov. Veniamin Kondratyev said that hundreds of Ukrainian drones attacked Novorossiysk, Anapa and Gelendzhik and the Temryuk district of the region overnight.

Russian air defences downed more than 500 Ukrainian drones, the Defence Ministry in Moscow said.

काला सागर

काला सागर

YouTube Homework

- Other Sea

अन्य सागर

कैस्पियन सागर
भूमध्य सागर
लाल सागर

महत्वपूर्ण तथ्य

- **काला सागर (Black Sea)** पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया के बीच स्थित एक महत्वपूर्ण **अंतर्देशीय समुद्र (Inland Sea)** है।

मुख्य तथ्य

- **सीमावर्ती देश (6 देश):** तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रूस और जॉर्जिया। *(याद रखने की ट्रिक: **BURGER**)*
- **जुड़ाव:** यह **बॉस्फोरस और डार्डनेल्स जलडमरूमध्य** (Straits) के माध्यम से भूमध्य सागर (Mediterranean Sea) से जुड़ता है।
- **अनोखी खासियत:** इसके 90% निचले पानी में **ऑक्सीजन नहीं है (Anoxic Water)**, इसलिए गहराई में समुद्री जीव नहीं रहते।
- **महत्व:** यह अनाज, तेल और गैस के समुद्री व्यापार का मुख्य रास्ता है और रूस-NATO के बीच सामरिक दृष्टि से बेहद संवेदनशील क्षेत्र है।

Overview

- CPGRAMS
- Financial Inclusion
- NCSC
- Inflation
- Justice Verma
- Mines & minerals Amendment Bill
- Ram Nath Kovind
- FCRA
- NFSA
- BNSS
- Black Sea

187 (1) (2) (3)

Thank You

Result Mitra